RNI Reg. No. CHHBIL/2020/80139
Volume- 04 Issue- 06
Bilingual Monthly (Hindi-English)

March 2024
Price- RS 20
32 Pages

Lok Shakti

लोक शक्ति

त्योहारों के इस देश में,
फिर आया है, लोकतंत्र का त्योहार

खीरे का सेवन करने से भारी भरकम तोंद की चर्बी गल जाएगी, फिट होते नहीं लगेगी देर

खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान की वजह से लोग इन दिनों मोटापे की चपेट में बहुत आसानी से आ रहे हैं। मोटापा जितनी तेजी से बढ़ता है उसको कम करना उतना ही मुश्किल काम है। मोटापे को कम करने के लिए लोगों को अपनी जीवनशैली और खानपान में सुधार करना होगा। खासकर, लोगों को अपनी डाइट पर ख़ासा ध्यान देना होगा। बेहतरीन डाइट और वर्कआउट की मदद से मोटापे को हराया जा सकता है। इसलिए मोटापे को कम करने के लिए आप अपनी डाइट में खीरा शामिल कर सकते हैं। पेट की बढ़ती चर्बी और मोटापे को कंट्रोल करने में खीरा बेहद असरदार है। बस आपको पता होना चाहिए इसका कब और कितना सेवन करना है।

- **पोषक तत्वों से भरपूर है खीरा**

एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर खीरे में 90% पानी होता है। इसमें प्रोटीन,विटामिन सी, फाइबर, विटामिन के और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। खीरा में कैलोरी भी काफी कम मात्रा में होती है इसलिए जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उनके लिए इसका सेवन करना फायदेमंद साबित हो सकता है।

डाइट में इन तीन तरीकों से करें खीरे का इस्तेमाल:

खीरा का डिटॉक्स वाटर: खीरे का डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को स्लाइस के रूप में कांटे। अब एक ग्लास में पानी लें और उसमें खीरे की स्लाइस, पुदीना और नींबू भी मिलाएं। इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखने के बड़ा यह पाने रोज़ना पियें। इस पानी को पीने से सिर्फ बॉडी ही डिटॉक्स नहीं होती बल्कि आपका मेटाबोइलज़ाम भी तेजी से बढ़ता है जिससे आपका वजन कम होता है।

खीरे का सलाद: आप अपनी डाइट में रोज़ाना खीरे का एक बाउल सलाद ऐड ऑन करें। खीरा, टमाटर और चुकंदर में नमक, काली मिर्च और नींबू के रस के साथ ऑलिव ऑयल मिलाएं। यह सलाद कैलोरी में कम और लंबे समय तक आपका पेट भरा रखता है। **खीरे का रायता:** अपना वजन कम करने के लिए आप दही में खीरे को बारीक काटकर जीरा पाउडर, काला नमक मिलाकर इसका रायता तैयार करें और हर दूसरे दिन शाम के समय इसका सेवन करें।

इन तरीकों से आप खीरा को खाएं साथ ही हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी फूड्स, नियमित व्यायाम और एक्सरसाइज़ करें। ऐसा कुछ ही दिन करने से आपका वजन तेजी से कम होगा।

Lok Shakti

EDITOR-IN-CHIEF Premendra Agrawal
EXECUTIVE EDITOR Rajesh Agrawal
MANAGING EDITOR Mr. Subhash
GROUP CREATIVE EDITOR Anjana
CHIEF ART DIRECTOR Deepika
FOREIGN EDITOR(US) Jamuna
CHIEF DESIGNER Vineeta Agrawal

RNI: CHHBIL/2020/80139

BUSINESS OFFICE

CHIEF EXECUTING OFFICER Satyabhama Agrawal
GENERAL MANAGER Vinod Agrawal
PUBLISHER Premendra Agrawal
MARKETING DIRECTOR Mr. Subhash
PHOTOGRAPHER Pawan Kumar
DIGITAL Tejas Agrawal
CHIEF PHOTO RESEARCHER Krisha

HEAD OFFICE

LOK SHAKTI, Agrasen Marg
Ramsagarpara, Raipur,
Chhattisgarh - 492001 (INDIA)
Whatsapp : 9926022174
e-mail: lokshakti.india@gmail.com

Printed and published by Premendra Agrawal
Editor: Premendra Agrawal.
Printed at Commercial Services
Agrasen Marg, Ramsagarpara, Raipur (CG).
Published from LOK SHAKTI, Agrasen Marg
Ramsagarpara, Raipur (CG).

YEAR : 04; ISSUE : 06
Published for the Month March, 2024
Released on March, 2024

Total no. of pages 32, including Covers

SCAN AND SHARE

Read Lok Shakti on your smart phone instantly. Point your phone's scanner on the code above and align it in the frame. You will be guided instantly to www.lokshakti.in.

NAVIGATOR

22 COVER STORY
लोकतंत्र का पर्व

30 सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनाने का प्रस्ताव
19 अपने ही पालतू आतंकियों पर UN में सवाल उठा रहा पाक
20 Iran Carry Out A Surgical Strike on Pakistan

02 खीरे का सेवन
05 दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन
08 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
09 डिजिटल इंडिया अभियान
10 जीडीपी वृद्धि
12 जम्मू-कश्मीर
14 आर्थिक सहायता
16 महिलाओं को मिली खुशियों की गारंटी
17 आर्थिक आजादी देगी महतारी वंदन योजना
18 बीमारू राज्य' के 'कलंक' को योगी सरकार ने धोया
24 मेट्रो
25 सैन्य अभ्यास
26 अंतरिक्ष
28 कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर

Message from Executive Editor's

We welcome you to our monthly magazine! You will find contents from across sectors including Politics, Education, Health, Economics among others. We have a great emphasis on Opinions, News & Analysis along with hints and Events from across the globe.

We want our publication to be valuable for you so please, do share your feedback and suggestions to help us improve. We have signed you up for our monthly magazine in the hopes that you will find great value in its content. Lok Shakti's publication comes with promise of great growth and change.

With each passing year, Interests and taste change, economies and leadership rise and fall, children age and grow … in truth it sees perhaps the most change of all.

…The media is simply a tool, and it's our job to help you use it in the way that's right for you as well as for the country and the world.

Sincerely,
Rajesh Agrawal
Executive Editor

सम्पादकीय

लोकतंत्र का पर्व है, करें मतदान

लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन, यही लोकतंत्र की परिभाषा है और इस परिभाषा को पूर्ण करने के लिए हमें जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसे मतदान कहा जाता है। मतदान के इस पर्व को जब हम उत्सव की भांति मनाना शुरू कर दें तो जाहिर है कि इस लोकतंत्र के पर्व में हम देश के अंतिम व्यक्ति तक को जोड़ सकते हैं। मतदान को अगर लोकतंत्र की आत्मा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मतदाता ही सबसे मजबूत और सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करता है। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इतने बड़े देश में पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से मतदान होना कई विकसित देशों के लिए भी आश्चर्य का विषय रहा है। भारत का गरीब से गरीब और सबसे अमीर व्यक्ति भी लोकतंत्र के इस महा यज्ञ में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि भारत विविधता के कारण भी एकता के सूत्र में पिरोया नजर आता है। यहां लोकतंत्र की ताकत है कि एक आम आदमी कब सत्ता हासिल कर ले, कोई नहीं जानता। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब देश के निम्न तबके के लोगों ने भी सत्ता हासिल करके लोकतंत्र की परिभाषा को परिपूर्ण किया है।

जब अधिक लोग मतदान में हिस्सा लेंगे तो एक कुशल नेतृत्व की पहचान की जा सकती है और चयन भी सही होगा। अत: ये परम आवश्यक है कि जब भी मतदान का उत्सव मनाया जाए, उसे पूरी निष्ठा के साथ हर नागरिक निभाए और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करे। हिमाचल प्रदेश ने कई राज्यों के सामने उदाहरण पेश किए हैं। हिमाचल का मतदाता पढ़ा लिखा और जागरूक है। यहां गांव में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी को समझता है। यही कारण है कि चुनाव के समय लोग घरों से निकलते हैं और मतदान के लिए आगे आते हैं।

चुनाव में सभी वर्ग के लोगों को आगे आकर वोट करना होगा। इसमें युवाशक्ति को अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। सभी को वोट डालने के लिए प्रेरित करें। बिना किसी दबाव में सोच समझकर वोट करें। यह एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। आप अपने बूथ पर जाकर निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर मतदान करें।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने पिछले एक दशक में सुशासन, सुरक्षा, सभी वर्गों के कल्याण व सांस्कृतिक विरासतों के पुनर्निर्माण का ऐतिहासिक दशक देखा है। भारत की विकास यात्रा की गति को ऐसे ही बनाए रखने के लिए अपना मत ऐसे नेतृत्व को दें, जिसके पास काम करने का ट्रैक रिकार्ड भी हो और भारत को विकसित बनाने का विजन भी। पिछला दशक उन लोगों द्वारा पैदा की गई कमियों को भरने के बारे में था जिन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया। "यह आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के बारे में भी था कि हाँ, भारत समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। हम इस भावना को आगे बढ़ाएंगे।" मोदी ने आगे कहा कि सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और भी तेज गति से जारी रहेगी। "हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने जा रहे हैं। हम युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत करेंगे।"

पूर्वोत्तर के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का

दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, उन्हें नए अवसर देना ये बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। नॉर्थ ईस्ट की बहनों को मदद करने के लिए कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की और कमी कर दी। नॉर्थ ईस्ट में हर घर नल से जल पहुंचाने का काम भी बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। आज यहां अरुणाचल प्रदेश में 45 हज़ार परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। अमृत सरोवर अभियान के तहत भी यहां अनेक सरोवर बनाए गए हैं। हमारी सरकार ने गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का भी बहुत बड़ा अभियान चलाया है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नॉर्थ ईस्ट की हजारों बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब हमारा लक्ष्य देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। इसका भी बड़ा फायदा नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को होगा, बहनों-बेटियों को होगा।' कनेक्टिविटी और बिजली, ये ऐसे काम हैं, जो जीवन भी आसान बनाते हैं और कारोबार भी आसान बनाते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक, नॉर्थ ईस्ट में, ये आंकड़ा याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट में 10 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, यानि 7 दशक में। जबकि बीते 10 वर्षों में, सिर्फ 10 वर्षों में 6 हजार किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। जितना काम 7 दशक में हुआ उतना मैंने एक दशक में करीब-करीब करके दिया है। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में करीब 2 हजार किलोमीटर नई रेल लाइन्स बनी हैं। पावर सेक्टर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। आज ही अरुणाचल में दिबांग मल्टीपरपज़ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरु हुआ है। दिंबाग डैम, देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है। यानि भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'एक तरफ मोदी, विकसित भारत के निर्माण के लिए एक-एक ईंट जोड़कर, युवाओं के बेहतर फ्यूचर के लिए दिन-रात काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने, जब ये मैं काम कर रहा हूं ना तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं।

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत किस तरह एक के बाद एक रिकार्ड कायम कर रहा है उस पर एक नजर-

अरुणाचल में दुनिया की सबसे लंबी बाइलेन सेला टनल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेला टनल का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन किया। यह दुनिया की सबसे लंबी बाइलेन टनल है। असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित सुरंग की आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी, 2019 में रखी थी। इससे तेजपुर से तवांग तक यात्रा के समय में एक घंटे से अधिक की कमी आएगी। केंद्र के सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की इस परियोजना में दो सुरंगें और एक लिंक रोड शामिल है। सुरंग 1, 980 मीटर जबकि सुरंग 2, 1.5 किमी लंबी है जिसमें यातायात और आपातकालीन सेवाओं के लिए एक बाईलेन ट्यूब होगी। दोनों सुरंगों के बीच 1,200 मीटर लंबी लिंक रोड होगी। तवांग जिले को शेष अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाली यह सुरंग हर मौसम में आवागमन के लिए उपलब्ध रहेगी। सेला सुरंग भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस सुरंग से चीन बॉर्डर पर आर्मी का मूवमेंट आसान हो जाएगा। इस सुरंग के जरिए हर मौसम में भारतीय सेना और उनके जरूरत के सभी सामान आसानी से पहुंच सकेंगे। सीमा सड़क संगठन ने इस सुरंग को बनाने में 825 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस सुरंग से रोजाना लगभग 3 हजार छोटी गाड़ियां और लगभग 2 हजार बड़े ट्रक और वाहन आवाजाही कर सकते हैं।

कच्छ के रण में दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट

गुजरात के कच्छ जिले के रण में भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे खावड़ा गांव में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्युएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है, जिससे 30 हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा। खास बात यह है कि 726 वर्ग किमी क्षेत्र में बना ये एनर्जी पार्क अंतरिक्ष से भी नजर आएगा। इस पार्क से लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ घरों को स्वच्छ बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में इस पार्क की नींव रखी थी। रण में बन रहा यह हाइब्रिड रिन्युएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे जहां कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तो वहीं भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी हो जाएगा। इस साल दिसंबर तक 50 प्रतिशत काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके साथ ही 14 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। जबकि दिसंबर 2026 में हाइब्रिड रिन्युएबल एनर्जी पार्क पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

देश का सबसे लंबा समुद्र से गुजरने वाला ब्रिज मुंबई में तैयार - देश का सबसे लंबा समुद्र से गुजरने वाले ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किमी है। यह ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानि अटल सेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 4B पर सेवरी से शुरू होगा और शिवाजी नगर, जस्सी और चिरले में इंटरचेंज होगा। यह ब्रिज आने वाले दिनों में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इस ब्रिज का 16.5 किमी का हिस्सा समुद्र में से होकर गुजरता है और 5.5 किमी का हिस्सा जमीन पर से गुजरता है। यह ब्रिज 6 लेन का है, जिसमें से 3 लेन आने और 3 लेन जाने के लिए होगी। इस ब्रिज पर 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे। साथ ही रोजाना 70 हजार से ज्यादा वाहन इसपर से गुजर सकेंगे। इस ब्रिज की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपये है और इस पर निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस कैमरा लगाए गए हैं, जो वाहनों की जानकारी और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इससे दो घंटे का सफर इस पुल के जरिए सिर्फ 35 मिनट में पूरा हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में मुंबई के शिवड़ी से न्हावासेवा के बीच 22 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण की आधारशिला रखी थी।

शिव नटराज की यह मूर्ति अनंत शक्ति का प्रतीक है। ईश्वर का यह स्वरूप धर्म, दर्शन, कला, शिल्प और विज्ञान का समन्वय है।

भारत मंडपम दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में शामिल -

दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत का ITPO कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में शामिल हो गया है। यह जर्मनी के हनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। यह कॉम्प्लेक्स ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सिडनी ओपेरा हाउस से अधिक बड़ा है। ओपेरा हाउस में जहां तकरीबन 5,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है वहीं ITPO कॉम्प्लेक्स में 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस तरह यह जर्मनी के हनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। इस कन्वेंशन सेंटर को वैश्विक पैमाने पर बड़े सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान बनाती है। प्रदर्शनी सभागारों में उत्पाद, नवोन्मेष और नये विचारों का प्रदर्शन करने के लिए यह आधुनिक स्थल हैं।

सूरत की डायमंड एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग

गुजरात का सूरत शहर वैसे तो अपने डायमंड कारोबार के लिए जाना जाता है लेकिन अब सूरत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। सूरत में चार साल में तैयार हुए सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज के ऑफिस ने अमेरिका के पेंटागन की बिल्डिंग को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के पेंटागन को अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग माना जाता था। यानि कि इस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कर्मचारी एक साथ काम करते थे लेकिन अब सूरत के डायमंड एक्सचेंज को ये तमगा मिला है। पेंटागन को पीछे छोड़कर डायमंड एक्सचेंज की बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है।

हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म - दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म भारत के कर्नाटक राज्य के हुबली में है, जिसकी कुल लम्बाई 1,505 मीटर है। इससे पहले उत्तरप्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है लेकिन अब यह प्लेटफार्म दूसरे नंबर पर आ गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। यानी यह डेढ़ किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है।

पीएम मोदी ने 12 मार्च 2023 को इस प्लेटफॉर्म को देश को समर्पित किया है। इस रेलवे स्टेशन का पूर नाम सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन है।

कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्ज हो गया है। यह भारतीय रेलवे में दक्षिण-पश्चिम रेलवे जोन का जंक्शन है। पीएम मोदी ने इस पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन को देश को समर्पित किया है।

दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' - देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में तैयार 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे विशालकाय प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर इसका अनावरण किया। खास बात ये है कि 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के अनावरण के लिए देशभर की 30 छोटी-बड़ी नदियों का जल लाया गया था, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र आदि शामिल हैं। पीएम मोदी ने इन्हीं 30 नदियों के जल से प्रतिमा के पास स्थित शिवलिंग का अभिषेक किया। इस दौरान 30 ब्राह्मणों ने मंत्रों का जाप भी किया। मूर्ति के निर्माण में 70,000 टन सीमेंट, 18,500 टन मजबूत लोहा, 6,000 टन स्टील और 1,700 मीट्रिक टन कांसे का प्रयोग किया गया है।

विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम - विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसका उद्घाटन 2020 में किया गया और इसमें 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जो दुनिया के किसी भी क्रिकेट स्टेडियम की तुलना में सबसे अधिक है। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नरेन्द्र मोदी स्टेडियम को 700 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है जो कि 63 एकड़ पर फैला एक विशाल मैदान है। इस मैदान में 76 कार्पोरेट बॉक्स, 4 ड्रेसिंग रूम के अलावा 3 प्रेक्टिस ग्राउंड भी बनाया गए हैं। एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम वाला यह दुनिया का पहला स्टेडियम हैं, बारिश का पानी को बाहर निकलने के लिए यहां आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया हैं, जिसके चलते यहां बारिश बंद होने के आधे घंटे के भीतर मैच मैच शुरू किया जा सकता है।

विश्व की सबसे लंबी सुरंग- अटल सुरंग - अटल सुरंग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। यह टनल मनाली को लेह से जोड़ती है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है और यात्रा के समय को भी 4 से 5 घंटे कम कर देती है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि मनाली को पूरे साल लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुरंग को समुद्र तल से 3,000 मीटर (10,000 फीट) की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है। टनल के भीतर सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। यह करीब 10.5 मीटर चौड़ी और 5.52 मीटर ऊंची है। पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया इसका उद्घाटन किया था। यह देश की पहली ऐसी सुरंग है जिसमें मुख्य सुरंग के भीतर ही बचाव सुरंग बनाई गई है। दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10 हजार फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग' के रूप में प्रमाणित किया गया है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हाथी और जीप पर सवार होकर जंगल सफारी का आनंद लिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। जंगल सफारी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज सुबह मैं असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में था। सघन हरियाली के बीच, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक सींग वाले गैंडे सहित विविध वनस्पतियों और वन्य-जीवों से समृद्ध है।

डिजिटल इंडिया अभियान ने

कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 8 मार्च को दिल्ली के भारत मंडपम में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, '10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स तक, डिजिटल इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया कि कब तक बैठे रहोगे इसके लिए भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है, तो भारत के मेरे युवा मन को हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है।'

कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। लोकगायिका मैथिली ठाकुर को कल्चरल एंबेसेडर ऑफ द ईयर अवॉर्ड, यूट्यूबर कामिया जानी को बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड और अमन गुप्ता को सेलिब्रिटी क्रिएटर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। गेमिंग श्रेणी में निश्चय को सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का पुरस्कार प्रदान किया। स्वास्थ्य और फिटनेस क्रिएटर का पुरस्कार अंकित बैयानपुरिया जबकि शिक्षा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार नमन देशमुख को दिया गया।

अवार्ड समारोह के दौरान स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से सम्मानित होने पर मल्हार कलांबे ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ सफाई से संबंधित वीडियो बनाना चाहते हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको मौका मिलेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है, इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है। लेकिन आपने भविष्य को पहचाना और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। अब ये श्रद्धा को देखिए खुद अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती है। अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर यानि आपको ही सबकुछ करना होता था। यानि एक प्रकार से इतना टैलेंट एक जगह पर जमा हो जाए और फिर जब वो प्रकट हो तो उसका सामार्थ्य कितना हो सकता है अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होने कहा कि आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपेक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के MVP. ठीक है ना थोड़ा दिमाग खपाओ Creativity बताओ अपना जब मैं आपको MVP कहता हूं मतलब Most Valuable Persons बन गए हैं।

क्रिएटर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'एक जमाने में हम छोटी से छोटी दुकानों पर लिखा देखते थे कि यहां बहुत टेस्टी फूड मिलता है। ऐसा देखते थे ना, कोई भी कहता कि यहां क्यों खाते हैं तो कहते थे कि यहां टेस्टी फूड है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुकानवाले लिखते हैं कि यहां हेल्दी फूड मिलता है। अब टेस्टी नहीं लिखता है हेल्दी फूड मिलता है ये क्यों बदलाव आया। तो ये बदलाव समाज में भी आ रहा है। इसलिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों में कृतज्ञ भाव जगाए, देश के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं, उनके लिए लोगों को प्रेरित करे।'

उन्होंने कहा, 'मैं तो रील बनाने के लिए समय नहीं निकाल सकता तो मैं ऐसे काम कर लेता हूं, लेकिन आप तो वो भी कर सकते हैं जी। क्या हम ऐसा कंटेंट और ज्यादा बना सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट को लेकर अवेयरनेस लाए। हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव-वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ कूल फॉर यूथ। वरना क्या है यार कुल... हॉस्टल में बैठे हैं कुल... साथियों इसमें बहुत बड़ा और आप लोग हैं... क्योंकि आप उनके साथ जुड़ सकते हैं उनकी भाषा में बात कर सकते हैं।'

2031 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत

मूडीज ने जीडीपी वृद्धि अनुमान बढ़ाकर किया 8 प्रतिशत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और दुनियाभर की तमाम रेटिंग एजेंसियों की माने तो ये मजबूती आगे भी कायम रहेगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि महंगाई में कमी आ रही है। बेहतर कृषि उत्पादन, खाद्य महंगाई पर नियंत्रण के साथ तेल और कमोडिटी की कीमतों में नरमी से वित्त वर्ष 2025 में भी यह गिरावट जारी रहेगी। क्रिसिल ने भारत आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि 2031 तक भारत उच्च-मध्यम आय वाला देश बन जाएगा और अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। एजेंसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीश मेहता ने यह भी कहा है कि इस दशक के अंत तक देश की प्रति व्यक्ति आय 4,500 डॉलर के स्तर को पार कर जाएगी।

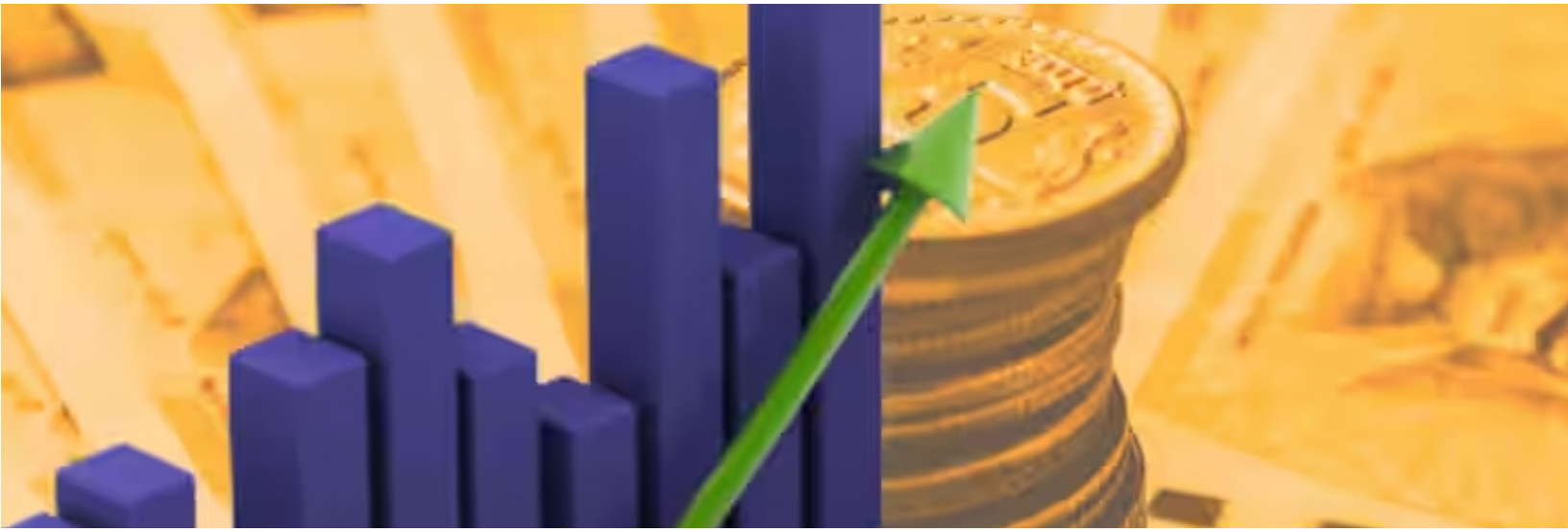

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और दुनियाभर की तमाम रेटिंग एजेंसियों की माने तो ये मजबूती आगे भी कायम रहेगी। अब दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश की आर्थिक तरक्की का अनुमान एक बार फिर बढ़ा दिया है। मूडीज ने 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। मूडीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पूंजीगत व्यय और घरेलू खपत में तेजी को देखते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर करीब 8 प्रतिशत कर दिया है। मूडीज का यह भी कहना है कि भारत जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

2031 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत- क्रिसिल

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि महंगाई में कमी आ रही है। बेहतर कृषि उत्पादन, खाद्य महंगाई पर नियंत्रण के साथ तेल और कमोडिटी की कीमतों में नरमी से वित्त वर्ष 2025 में भी यह गिरावट जारी रहेगी। क्रिसिल ने भारत आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि 2031 तक भारत उच्च-मध्यम आय वाला देश बन जाएगा और अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। एजेंसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीश मेहता ने यह भी कहा है कि इस दशक के अंत तक देश की प्रति व्यक्ति आय 4,500 डॉलर के स्तर को पार कर जाएगी।

भारत की जीडीपी ग्रोथ 8 प्रतिशत तक पहुंचने की ओर अग्रसर- बार्कलेज रिसर्च

बार्कलेज रिसर्च ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 8 प्रतिशत तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। बार्कलेज रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि उचित पॉलिसी मिक्स के साथ भारत संभावित रूप से अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को 8 प्रतिशत के करीब बढ़ा सकता है और इस दशक के अंत तक ग्लोबल ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन सकता है। इंडियाज ब्रेकआउट मोमेंट शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती घरेलू बचत और सार्वजनिक गैर-बचत में गिरावट से घरेलू बचत को उस स्तर से ऊपर बढ़ाया जा सकता है जो अर्थव्यवस्था की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बार्कलेज रिसर्च ने यह भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर तीन प्रमुख सब-सेक्टर्स में सबसे तेज ग्रोथ दिखाएगा।

2023 से 2028 के बीच औसत 6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी इंडियन इकोनॉमी

गोल्डमैन सैश ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 से 2028 के बीच औसत 6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। गोल्डमैन सैश ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 और 2028 के बीच सालाना 6 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि करेगी, साथ ही देश में समृद्ध उपभोक्ताओं की संख्या 2023 में 60 मिलियन से बढ़कर 2027 तक 100 मिलियन हो जाएगी। गोल्डमैन सैश के विश्लेषक अर्नब मित्रा ने कहा है कि यदि धन प्रभाव मजबूत होता है, तो यह और भी अधिक हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्रेडिट कार्ड की संख्या में लगभग 14-15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमने 1 मिलियन रुपये से अधिक की टैक्स फाइलिंग देखी, ये लगभग 19 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

2075 तक भारत बनेगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था- गोल्डमैन सैश

हाल ही में आई गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2075 तक दूनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। गोल्डमैन सैश के रिसर्च इकोनॉमिस्ट शांतनु सेनगुप्ता के मुताबिक भारत की आबादी में दुनिया की आबादी की तुलना में सबसे बेहतरीन मिश्रण मौजूद है। कामगारों, बच्चों और बुजुर्गों की आबादी भारत में अन्य देशों की तुलना में सबसे अच्छी है। इस कारण भारत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर काम किया है। ये दोनों ही क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद कर रहा है।

2024-25 में 7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी- RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मॉनेटरी पॉलिसी का एलान करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024-25 में 7 प्रतिशत से दर से बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से मिले-जुले संकेत ही मिल रहे हैं। अस्थिर ग्लोबल स्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही निजी निवेश में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि ग्रामीण मांग में तेजी जारी है, शहरी खपत मजबूत बनी हुई है और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण निवेश चक्र रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जून तिमाही में ग्रोथ रेट के 7.2 प्रतिशत, सितंबर तिमाही में 6.8 प्रतिशत, दिसंबर तिमाही में 7 प्रतिशत और मार्च तिमाही में 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्तवर्ष 2025 में 6.5 प्रतिशत रह सकती है देश की ग्रोथ रेट- आईएमएफ

वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष में भी वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है। इसमें 40 आधार अंक बढ़ाते हुए 6.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2024 (वित्त वर्ष 2025) और 2025 (वित्त वर्ष 2026) में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है और दोनों वर्ष के वृद्धि अनुमान को अक्टूबर में लगाए गए अनुमान से 0.2 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जो मजबूत देसी मांग के कारण है।

2027-28 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा- आईएमएफ - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान व्यक्त किया, उसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था, जो अभी लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। भारत 5.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। इस दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था 31 ट्रिलियन डॉलर के साथ शीर्ष पर रहेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत होगी। इसके बाद चीन 25.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहेगा और वैश्विक जीडीपी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

ग्लोबल ग्रोथ में भारत की होगी 18 प्रतिशत हिस्सेदारी- आईएमएफ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का मानना है कि भारत विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का योगदान अगले पांच साल में मौजूदा 16 प्रतिशत बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा। आईएमएफ के एशिया-प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन के अनुसार 2028 तक दुनिया की विकास दर में भारत की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत होगी। आईएमएफ का मानना है कि बड़े पैमाने पर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है।

चुनौतियों के बाद भी सबसे तेज रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि

भारत आने वाले समय में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार रूस-यूक्रेन संकट, कोरोना महामारी और महंगाई जैसी चुनौतियों के बाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी 2028 तक फ्रांस और ब्रिटेन को पार कर जाने की उम्मीद है। इससे भारत वैश्विक आर्थिक विकास को चलाने में एक प्रमुख देश बन जाएगा।

आईएमएफ को भरोसा, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगुवाई करेगा भारत

आईएमएफ का कहना कि भारत की अगुवाई में दक्षिण एशिया वैश्विक वृद्धि का केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है और 2040 तक वृद्धि में इसका अकेले एक-तिहाई योगदान हो सकता है। आईएमएफ के हालिया शोध दस्तावेज में कहा गया कि बुनियादी ढांचे में सुधार और युवा कार्यबल का सफलतापूर्वक लाभ उठाकर यह 2040 तक वैश्विक वृद्धि में एक तिहाई योगदान दे सकता है। आईएमएफ की एशिया एवं प्रशांत विभाग की उप निदेशक एनी मेरी गुलडे वोल्फ ने कहा कि हम दक्षिण एशिया को वैश्विक वृद्धि केंद्र के रूप में आगे बढ़ता हुए देख रहे हैं।

कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है भारत

इसके पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) की उपप्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कई दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत को लेकर दुनियाभर में पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बहुत सारे बिजनेस और कंपनियां भारत को एक निवेश डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं, क्योंकि वे चीन सहित दूसरे देशों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत- फिच

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों का कमाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का हर सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आज भारत विकास दर के मामले में दुनिया में नंबर वन बना हुआ है। देशी और विदेशी रेटिंग एजेंसियां भी भारत के विकास दर पर भरोसा जता रही हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच (Fitch) ने भारत की रेटिंग को बरकरार रखते हुए कहा कि अगले कुछ सालों तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। फिच ने भारत के लिए 'बीबीब-'(BBB-) की रेटिंग बरकरार रखी है और विकास दर के अनुमान में बढ़ोतरी की है। एजेंसी के अनुसार, भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 6.9 प्रतिशत के दर से बढ़ सकती है, जो मई 2023 में किए गए अनुमान 6 प्रतिशत से काफी ऊपर है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी में 6.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था।

जीडीपी ग्रोथ 6.9 से 7.2 प्रतिशत की बीच रहने की संभावना- डेलॉयट

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9 से 7.2 प्रतिशत की बीच रहने की संभावना है। डेलॉयट इंडिया की तिमाही रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अलग ही मोमेंटम बन रही है। इससे भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में 6.9 से 7.2 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 6.4 से 6.7 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आर्थिक बुनियाद में सुधार के कारण है। डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा है कि आर्थिक बुनियाद में सुधार ने हमारी धारणा को मजबूत किया है और हमें उम्मीद है कि हमारे आधारभूत परिदृश्य में जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2023-24 में 6.9 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहेगी।

ये नया जम्मू-कश्मीर है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज, 7 मार्च को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस जम्मू-कश्मीर का इंतजार हम सभी को दशकों से था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'ये वो नया जम्मू-कश्मीर है, जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू-कश्मीर है, जिसके लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू-कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू-कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके ये मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है, और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज जम्मू-कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर आज खुलकर के सांस ले रहा है। बन्दिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था, या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे, जम्मू-कश्मीर की अवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू-कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसीलिए जम्मू-कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी हैं, समान अवसर भी हैं।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू-कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। लेकिन इन्हें देश, इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं- मैं हूं मोदी का परिवार!, मैं हूं मोदी का परिवार! मैंने जम्मू-कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसीलिए, कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि- मैं हूं मोदी का परिवार! मैं हूं मोदी का परिवार! मोदी अपने परिवार को ये विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के विकास का ये अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू-कश्मीर और तेजी से विकास करेगा।'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिये गए हैं। विकास की शक्ति...पर्यटन की संभावनाएं...किसानों का सामर्थ्य...और जम्मू-कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व...विकसित जम्मू-कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू-कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है। ये जम्मू-कश्मीर भारत का मस्तक है। और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए, विकसित जम्मू-कश्मीर, विकसित भारत की प्राथमिकता है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे, वो जम्मू-कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थीं…लेकिन जम्म-कश्मीर के मेरे भाई-बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए, वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। इसलिए जम्मू-कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए हैं, देश भी आज श्रीनगर से जुड़ा हुआ है।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई हैं। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू-कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आज प्रसाद योजना के तहत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, 14 और परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया है। पवित्र हजरतबल दरगाह में लोगों की सहूलियत के लिए जो विकास कार्य हो रहे थे, वो भी पूरे हो चुके हैं। सरकार ने 40 से ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान भी की है, जिन्हें अगले 2 वर्षों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा।

आज 'देखो अपना देश पीपल्स चॉइस' अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे, ये एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे, उनके लिए सरकार पसंदीदा, लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में, उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी।'

उन्होंने कहा, 'फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा दूसरा मिशन है- 'वेड इन इंडिया', शादी हिन्दुस्तान में करो। हिन्दुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाब-शनाब रूपये, डॉलर खर्च करके लोग आते हैं…जी नहीं, 'वेड इन इंडिया', अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग अब हमें 'वेड इन इंडिया' के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां आकर बुकिंग करें, यहां 3 दिन, 4 दिन बारात लेकर कर आएं, धूमधाम से खर्चा करें, यहां के लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी। उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। '

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू-कश्मीर में G-20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे- जम्मू-कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा? आज यहां जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से ढाई गुना बढ़ी है। अब बड़े-बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं, वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, और वायरल हो रही है।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू-कश्मीर की केसर, जम्मू-कश्मीर के सेब, जम्मू-कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू-कश्मीर अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5 हजार करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू-कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी।'

समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि 2-2 एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। AIIMS जम्मू का उद्घाटन हो चुका है, और AIIMS कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू-कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही हैं। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामुला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू-कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं के स्किल डवलपमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक में नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज जम्मू-कश्मीर के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं बनाई जा रही हैं। 17 जिलों में यहां मल्टी-परपज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाए गए हैं।

बीते वर्षों में जम्मू-कश्मीर ने अनेकों नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में मेजबानी की है। अब जम्मू-कश्मीर, देश की शीतकालीन खेल- Winter Games एक राजधानी- विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में ये मेरा जम्मू-कश्मीर उभर रहा है। हाल ही में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करीब एक हजार खिलाड़ी देशभर से आए, उन्होंने हिस्सा लिया।'

किसानों को खेती करने के लिए आर्थिक सहायता

MP में जिन किसानों ने कृषि साख सहकारी समितियों ऋण लिया हो उन किसानों के लिए अब नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अब चार हजार 536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से MP में लाखों किसानों के माध्यम से ऋण लिया गया जो प्रदेश सरकार ने सभी किसानों के हित में एक बड़ा ही निर्णय भी लिया है। ताकि प्रदेश भर के किसानों को फायदा भी मिल सके।

किसानों के लिए अच्छी खबर निकलकर आपके सामने आ रही जो की MP सरकार के किसानों को कम टाइम में उगाई जाने वाली फसलों के लिए बिना ब्याज के lone भी दिया जायेगा। जिसके वजह से सभी किसानों को खेती करने में भी सहायता दी जाएगी। जिसमे छोटे किसानों को बहुत भी अधिक फायदा भी होगा।MP सरकार के माध्यम से सभी किसानों को आर्थिक सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।

बता दे की MP में सभी किसानों को खेती करने के लिए प्रदेश सरकार बिना ब्याज के lone देती है। ताकि प्रदेश में गरीब किसान खेती करने के लिए उर्वरक खाद, बीज, कीटनाशक दवाई और भी अन्य चीजों को खरीद सके और खेती को आसान बना सके। अब ये आर्थिक सहायता की मदद से किसान खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ा भी सकते है। साथ-साथ किसान कम आमदनी में अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रदेश में ऐसे बहुत से किसान होंगे जिनके पास पैसे की कमी होने के वजह से अपनी खेती को अच्छे से नहीं कर पाते हैं।

राज्य खेल अलंकरण समारोह का 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में पुनः आयोजन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 5 साल के अंतराल के बाद 14 मार्च 2024 को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया। खेल अलंकरण समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की। खेल अलंकरण समारोह, जो राज्य के एथलीटों की उपलब्धियों को चिन्हित करते हुए उन्हें सम्मानित करता है, को भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था।

छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण समारोह की शुरुआत डॉ. रमन सिंह की सरकार के दौरान हुई थी। राज्य खेल अलंकरण समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य के एथलीटों की उपलब्धियों का सम्मान और पहचान करना और राज्य में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

2019-20 और 2020-21 में उनकी उपलब्धियों के लिए राज्य के कुल 544 एथलीटों को सम्मानित किया गया। विजेताओं को नकद पुरस्कार, एक मानक प्रमाण पत्र, एक सजावट पट्टिका, एक ब्लेज़र और एक टाई प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना

इस अवसर को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पारंपरिक खेलों को, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की है।

राज्य सरकार ने योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। सरकार इस योजना के तहत जशपुर जिले के कुनकुरी में अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण कराएगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवासीय खेल अकादमियाँ स्थापित की जाएंगी। रायगढ़ और बलौदाबाजार जिले में इनडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के लिए 31 वें खेलो इंडिया सेंटर को मंजूरी

इस अवसर पर बोलते हुए, राज्य के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया की कि केंद्र सरकार ने राज्य में 31 वें खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

भारत सरकार ने राज्य के बिलासपुर जिले में हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर को भी मंजूरी दे दी है।

खेलो इंडिया केंद्रों में, सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, खेल उपकरण और ड्रेशों के लिए सालाना 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ-साथ कोच को 25,000 रुपये का मासिक मानदेय प्रदान करेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार के खेल पुरस्कार

शहीद राजीव पांडे पुरस्कार

शहीद राजीव पांडे पुरस्कार राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पदक जीता हो या किसी अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार विजेता को 3 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।

शहीद कौशल यादव पुरस्कार

जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया जाता है। विजेता को 1.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार

पिछले 5 वर्षों में 4 बार सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित किया जाता है। पंकज विक्रम सम्मान के विजेता को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

वीर हनुमान सिंह पुरस्कार

राज्य के प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों अथवा खेल निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उन्हे 1.50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

महतारी वंदन योजना :

महिलाओं को मिली खुशियों की गारंटी

आलेख

श्रीमती रीनू मिश्रा
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दी गई गारंटी को पूरा कर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई सरकार ने महिला सशक्तिकरण का एक नया रास्ता तैयार किया है। इससे महिलाओं में भारी उत्साह है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को 12 हजार रूपए वार्षिक भुगतान किये जाएंगे। इससे महिलाओं के खाते में हर माह डीबीडी के माध्यम से एक हजार रूपए आएंगे। इसका उपयोग वह अपनी जरूरत और इच्छा के अनुसार कर सकेंगी। इससे महिलाओं की छोटी-छोटी खुशियों को अब गारंटी मिल गई है।

महतारी वंदन योजना

महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई महतारी वंदन योजना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 3,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इससे महिलाओं की न सिर्फ रोजमर्रा की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी होंगी बल्कि उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं के उत्साह का प्रमाण है कि 05 फरवरी को आवेदन करने के पहले ही दिन 1 लाख 81 हजार से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया। दिन-प्रतिदिन योजना की लोकप्रियता के साथ फार्म भरने का सिलसिला भी बढ़ता रहा। योजना के तहत 20 फरवरी को अंतिम तिथि तक लगभग 70 लाख महिलाओं ने आवेदन जमा कर दिया। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद हितग्राहियों को दावा आपत्ति के लिए समय दिया गया। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अंतिम सूची के आधार पर पात्र महिला के खाते में मार्च माह में प्रथम बार राशि का अंतरण किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ की लगभग 70 लाख पात्र महिलाओं को लाभ होगा।

महिलाओं को मिली खुशियों की गारंटी

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का सुचारू क्रियान्वयन हो और बड़ी संख्या में आवेदन करने वाली महिलों को असुविधा न हो इसका ध्यान रखते हुए पुख्ता व्यवस्था की गई। राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया गया। जिला स्तर पर कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए। आवेदन के लिए ऑनलाईन पोर्टल https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ तथा मोबाईल एप बनाया गया।

पोर्टल में हितग्राहियों को आवेदन की स्थिति की जानकारी की सुविधा भी दी गई। साथ ही राज्य स्तर पर योजना से संबंधित समाधान के लिए टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1800233448 भी जारी किया गया। जिला प्रशासन द्वारा पात्रता संबंधी नियमों को बताने के लिए कर्मचारी नियुक्त किये गए। आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया गया। घर-घर सर्वे कर फार्म भरवाए गए। इसके साथ ही प्रतिदिन राज्य स्तर पर योजना की समीक्षा और निगरानी की जा रही है।

महिलाएं विशेषकर विवाहित महिलाएं घर-परिवार की देखभाल, प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएं अपनी छोटी-मोटी बचत का उपयोग ज्यादातर परिवार और बच्चों के पोषण में खर्च करती हैं। लेकिन आर्थिक मामलों में उनकी सहभागिता अभी भी बहुत कम है। इसे देखते हुए राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक सहभागिता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य की बात की जाए तो 2020-21 में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 के अनुसार 23.1 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर हैं। 15 से 49 वर्ष के आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 60.8 प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं में यह 51.8 प्रतिशत है। ऐसे में महतारी वंदन योजना उनके लिए बड़ी राहत बनकर आई हैं।

महिलाओं ने प्रतिमाह एक हजार रूपए मिलने से अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने की तैयारी भी कर ली है। धमतरी में रुद्री निवासी लोमेश्वरी ओझा कहती हैं कि मेरी छोटी-छोटी खुशियां इस राशि से पूरी होगी। मैं अपने बच्चों के लिए भी राशि खर्च कर सकूंगी। रायपुर की सविता साहू का कहना है कि कि तीज-त्यौहार में उन्हें, मायके से जो भेंट मिलती है, उसको वह मनचाहा खर्च करती हैं। ऐसे में मुझे मुख्यमंत्री श्री साय भी भाई की तरह लग रहे हैं, जो हर महीने तीज की राशि हजार रुपए देंगे। यह राशि महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के साथ परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका के सुदृढ़ीकरण में भी सहायक साबित होगी।

महतारी वंदन योजना से मिली राशि से महिलाओं को परिवार के साथ खुद के स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर को उठाने का एक मजबूत आधार मिलेगा। महिलाओं की आर्थिक मजबूती से समाज में उनके प्रति भेदभाव में कमी और जागरूकता आएगी। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की आधी आबादी की आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

महिलाओं को आर्थिक आजादी देगी महतारी वंदन योजना

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले महिलाओं के खाते में आएगी राशि

विशेष लेख - डॉ. दानेश्वरी संभाकर, सहायक संचालक

महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वो अपने को सकारात्मक भूमिका देने में अहम योगदान कर सकती है। जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से आज भारत देश विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। विकसित भारत बनाने के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए यहां की माताओं और बहनों का बड़ा योगदान रहने वाला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में तीज-त्यौहारों और खुशी में महिलाओं को तोहफे, पैसे और नेग देने का रिवाज है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से उसी परंपरा छत्तीसगढ़ शासन निभा रही है।

महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (क्ठज्) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के बीच लैंगिक भेदभाव, असमानता और जागरूकता के स्तर का बढ़ावा, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना है। इसका लाभ उन विवाहित महिलाओं को मिलेगा जो 1 जनवरी, 2024 तक 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथ छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएँ भी योजना के लिये पात्र हैं।

महिलाएं खुश है कि वो महतारी वंदन योजना से मिली राशि से अपने बच्चों और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी कर पाएगी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि 2024-25 बजट में उनकी सरकार का फोकस ळल्।छ यानि गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। बजट में सभी वर्गों की चिन्ता की गई है। यह बजट सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है, जो छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की परिकल्पना को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि उनका प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा। इसी लिए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन भरने के प्रथम चरण में लगभग 70 लाख महिला हितग्राहियों की अनंतिम सूची जारी की जा चुकी है एवं इनका प्रकाशन आंगनबाड़ी केंद्रों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले यानी 7 मार्च को इन महिलाओं के खाते में एक-एक हज़ार रुपए अंतरित की जाएगी।

यूपी के माथे पर 'बीमारू राज्य' के 'कलंक' को योगी सरकार ने धोया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के सात साल पूरे हो रहे हैं। दशकों तक 'बीमारू' राज्य की छवि रखने वाला प्रदेश आज देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन चुका है। विकसित भारत के जिस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने

यही नहीं उत्तर प्रदेश आज आत्मनिर्भर राज्य की ओर से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

निवेश ने दुनिया को चौंकाया

बीते सात साल में यूपी की प्रभावशाली विकास यात्रा पर हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 (जीबीसी) के जरिए देशभर के उद्यमियों ने 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करके अपनी मुहर लगा दी है। अगर अबतक हुए सभी चार जीबीसी की बात करें तो ये आंकड़ा तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए पहुंचता है। इतने भारी-भरकम निवेश से न केवल यूपी की आर्थिक समृद्धि को बल मिला है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी हुआ है। अकेले जीबीसी 4.0 से 34 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है।

'उद्योग प्रदेश' बना उत्तर प्रदेश

जनसंख्या के साथ विशाल कंज्यूमर बेस भी रखता है। यही कारण है कि इतना विशाल उपभोक्त बाजार निवेशकों को हर तरह से आकर्षित कर रहा है।

एक्सप्रेसवे प्रदेश बना यूपी

उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में एक्सप्रेसवे की चर्चा के बिना अधूरी है। जिस राज्य के बारे में 2017 से पहले ये कहा जाता था कि जहां से गडढों वाली सड़क शुरू हो, समझ लीजिए यूपी शुरू हो चुका है, आज ये वहीं प्रदेश है जहां देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे संचालित हैं। प्रदेश में आज 6 एक्सप्रेसवे क्रियाशील हैं, जबकि 7 निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें भी तकरीबन 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे इस साल के अंत तक बनकर तैयार होने जा रहा है।

सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश

अपने ही पालतू आतंकियों पर UN में सवाल उठा रहा पाक

पाकिस्तानी दूत ने चेतावनी दी कि टीटीपी पर लगाम लगाने में विफलता अंततः इसे वैश्विक आतंकवादी खतरा बना सकती है। अफगानिस्तान पर यूएनएससी के एक विशेष सत्र के दौरान, पाकिस्तानी राजदूत ने उल्लेख किया कि पाकिस्तान को पिछले साल 306 आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कश्मीर मुद्दे पर अक्सर भारत के खिलाफ मुखर रहने वाला पाकिस्तान अब अपने ही पाले हुए आतंकी संगठनों से दर्द झेल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इन समूहों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर होकर, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ संबंध तोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीटीपी की गतिविधियां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सक्रिय हैं और पाकिस्तान अफगान तालिबान पर प्रभाव होने का दावा करता है। पाकिस्तानी दूत ने चेतावनी दी कि टीटीपी पर लगाम लगाने में विफलता अंततः इसे वैश्विक आतंकवादी खतरा बना सकती है। अफगानिस्तान पर यूएनएससी के एक विशेष सत्र के दौरान, पाकिस्तानी राजदूत ने उल्लेख किया कि पाकिस्तान को पिछले साल 306 आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा, जिसमें 23 आत्मघाती बम विस्फोट शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 693 मौतें हुईं और 1,124 घायल हुए। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार, अकेले फरवरी में, पाकिस्तान में 97 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 87 मौतें हुईं और 118 घायल हुए।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में 78% आतंकवादी हमले टीटीपी द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि इन हमलों को पाकिस्तानी सरकार पर बातचीत के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में देखा जाता है। टीटीपी की हिंसा पर निर्भरता पाकिस्तानी सरकार पर दबाव डालती है। इन समूहों पर अफगान तालिबान का नियंत्रण इस दबाव में योगदान देता है, क्योंकि ये संगठन अफगान तालिबान द्वारा समर्थित महसूस करते हैं। पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने बताया कि अफगान सरकार तालिबान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि अन्य आतंकवादी समूह भी प्रमुखता हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान, जो पहले अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण से संतुष्ट था और इसे भारत की हार के रूप में चित्रित कर रहा था, अब उसे अपने ही पोषित आतंकवादी संगठनों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से, पाकिस्तान ने इन समूहों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अपना रुख बदल दिया। गौरतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पश्तून पहचान को लेकर लंबे समय से अलगाववाद चल रहा है, जबकि खैबर में पश्तूनों को अफगानिस्तान से समर्थन मिलता है।

Iran Carry Out A Surgical Strike on Pakistan

according to a report by AP, Pakistan's Air Force struck terrorist hideouts in Iran's Siestan-Balochistan province in retaliation, killing four children and three women.

"This morning Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Siestan-o-Balochistan province of Iran," Pakistan's Ministry of Foreign Affairs said in a statement .

This follows an air strike by Iran in Pakistan on Tuesday, triggered by an attack by the Jaish al-Adl terror group. Here is everything we know about the escalating conflict till now.

Iran breaches Pakistan's air defence system: What happened?

Iran breached Pakistan's air defence system, targeting two key strongholds of the terror outfit Jaish al-Adl in Balochistan using precision missile and drone strikes on Tuesday, January 16. This led to the tragic death of two children, according to Pakistani media reports. In a Telegram post, Jaish al-Adl claimed that Iran's Revolutionary Guards used six attack drones to destroy the homes of families of the terrorist group.

Later on Tuesday night, Pakistan's Ministry of Foreign Affairs stated that the attack was "unprovoked" and was a "violation" of its airspace. An official statement by the ministry, released on Wednesday, read that the attack had caused the death of two children and injured three girls.

“This violation of Pakistan's sovereignty is completely unacceptable and can have serious consequences," the statement read.

It added, "It is even more concerning that this illegal act has taken place despite the existence of several channels of communication between Pakistan and Iran... Pakistan has always said terrorism is a common threat to all countries in the region that requires coordinated action. Such unilateral acts are not in conformity with good neighbourly relations and can seriously undermine bilateral trust and confidence."

Why did Iran attack Pakistan?

Iran's military action was reportedly in retaliation to the death of 11 Iranian police force members killed by Jaish al-Adl in an attack on a police station in Sistan-Balochistan province in December 2023. Iran suspects that Pakistan, mainly due to its Sunni majority, harbours insurgents, possibly influenced by regional rival Saudi Arabia.

A similar attack had also taken place in July last year, where four policemen were killed while on duty. Two weeks before that, the Jaish al-Adl had also claimed responsibility for a shootout in the province of Sistan-Balochistan where two policemen and four assailants were killed, according to reports by Aljazeera.

Iran suspected that Sunni-majority Pakistan had provided a safe haven for the group. While Iran has carried out moves against terror groups in border areas, the air strike was unexpected.

Iranian ambassador expelled from Pakistan

While Iran has fought against terrorists in border areas, a missile-and-drone attack inside Pakistan is unprecedented. The attack occurred on the same day as a meeting between Iran's foreign minister and Pakistan's caretaker prime minister, raising concerns about communication breakdown.

On Wednesday, Pakistan decided to recall its ambassador from Iran and expelled the Iranian ambassador from the country in response to the drone strikes on alleged terror bases.

Background on Jaish al-Adl

Jaish al-Adl, meaning the Army of Justice, was formed in 2012. It is also called Jaysh al-Dhulm in Iran. Jaish al-Adl comprises Sunni militants from the Jundullah group. The group seeks independence for the ethnic Baloch community residing on both sides of the Iran-Pakistan border (Iran's Sistan and Pakistan's Balochistan provinces). This has made it a common target by both governments.

According to a report by Wion, Pakistan has maintained that Jaish al-Adl has no organised presence within its borders. However, it acknowledges the potential presence of militants in remote areas of Balochistan. The region, marked by a longstanding insurgency, remains sensitive due to separatist and nationalist sentiments. Moreover, both Iran and Pakistan have harboured suspicions about each other regarding militant attacks.

Has Pakistan's air space been breached before?

This isn't the first time Pakistan's airspace has been breached. Instances like the US operation against Osama bin Laden in 2011 and India's surgical strike in 2016 against the Jaish-e-Mohammed group were both instances of counter-terrorism operations.

India's stance on the Iran-Pakistan conflict

India has emphasised zero tolerance for terrorism. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal stated, "This is a matter between Iran and Pakistan. Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self defence."

China also released an official statement urging restraint for both countries and highlighting the importance of maintaining peace and stability.

2024 में सात चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव

लोकसभा चुनाव की प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनाव का बिगुल बजा दिया है। पूरे देश में सात चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 20 मार्च से होगी। 19 अप्रैल से 1 जून तक मतदान होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श चनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा के साथ-साथ चार राज्यों ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की है। तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना शुरू कर दिया था। बीजेपी उम्मीदवार घोषित करने में सबसे आगे रही है।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने आज (16 मार्च, 2024) को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। सात चरणों में मतदान होंगे। 20 मार्च, 2024 को पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख और 30 मार्च को उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 19 अप्रैल से मतदान की शुरुआत होगी। 4 जून, 2024 को नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल को पहला चरण, 26 अप्रैल को दूसरा, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को पांचवा चरण, 25 मई को छठा चरण और 1 जून को सातवां चरण होगा। 19 अप्रैल को सिक्किम, 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और 13 मई को आंध्र प्रदेश में एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं ओडिशा में चार चरणों 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून को मतदान होगा। देश के कई राज्यों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे।

लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक इस चुनाव में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जो कुछ महाद्वीपों के संयुक्त मतदाताओं से भी अधिक है। युवा मतदाताओं की संख्या 19.74 करोड़ है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरे देश में 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2100 पर्यवेक्षक चुनाव प्रकिया पर नजर रखेंगे। चुनाव प्रक्रिया में 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। मतदान के लिए 55 लाख से अधिक ईवीएम और 4 लाख वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे।

पहला चरण : 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी की कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

दूसरा चरण : 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान

असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटों पर मतदान होगा।

तीसरा चरण : 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान

असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली और दमन दीव की कुल 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

चौथा चरण : 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान

आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

पांचवां चरण : 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान

छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रेदश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की 49 सीटों पर मतदान होगा।

छठ चरण : 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान

बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा।

सातवां चरण : 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान

बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ की कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू - चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार के तहत चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता विकसित की है, जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए मानदंड स्थापित करती है।

इसका उद्देश्य सभी दलों को चुनाव लड़ने के लिए एक जैसे ही अवसर देना है। इसके लागू होते ही सरकारी घोषणाओं पर रोक लग गई है। इसके तहत मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या उसके वादे करने पर प्रतिबंध लग गया है। अब सिविल सेवकों को छोड़कर, मंत्री या नेता शिलान्यास करने और परियोजनाओं या योजनाओं की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में एड हॉक नौकरियां, जो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है, उस पर भी रोक लग गई है। चुनाव में विवादित बयान देने, फर्जी खबरों, जाति और धर्म के आधार पर मतदान के लिए अपील करने पर रोक लगाई गई है।

उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में बीजेपी सबसे आगे

राजनीतिक दलों ने आम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दो सूचियां जारी की हैं। अब तक बीजेपी 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 और दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं।

2019 में सात चरणों में हुए थे लोकसभा चुनाव

पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को की गई थी। चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच सात चरणों में करवाए गए थे। जबकि 23 मई को रिजल्ट आया था। उस चुनाव के वक्त देश में 91 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे, जिनमें 67 प्रतिशत ने वोट डाला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, एनडीए ने 353 सीटें हासिल की थीं। बीजेपी को 37.7 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि एनडीए को 45 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किए थे। कांग्रेस ने 2014 की तरह ही खराब प्रदर्शन किया और 52 सीटों से संतोष करना पड़ा।

2014 में नौ चरणों में हुए थे लोकसभा चुनाव - 2014 में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 मार्च को हुआ था। चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में हुए थे। चुनाव मैदान में 8,251 उम्मीदवार थे। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया था। वह स्वतंत्र भारत के 67 साल के इतिहास में जादुई संख्या को पार करने वाली पहली गैर-कांग्रेसी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं और मान्यता प्राप्त विपक्ष बनने के लिए लोकसभा में 10 प्रतिशत यानी 55 सीटें हासिल नहीं कर पाई थीं।

देश में पहली बार पानी के नीचे दौड़ी मेट्रो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई. ये मेट्रो कोलकाता से हावड़ा के बीच चलेगी. पीएम ने इस मेट्रो में स्कूली बच्चों के साथ सफर किया और उनसे बातचीत भी की. इस मेट्रो की खास बात यह है कि ये हुगली नदी के अंदर बनी टनल में चलेगी. पानी के अंदर बनी मेट्रो सुरंग इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि है, जो 16.6 किमी लंबी है.

पीएम मोदी ने किया देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन

अंडरवाटर मेट्रो हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को पूर्वी तट पर साल्ट लेक शहर से जोड़ेगी. इसमें 6 स्टेशन होंगे, जिनमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं. वहीं हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है. कोलकाता मेट्रो का हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड सेक्शन बेहद खास है, क्योंकि इस सेक्शन में ट्रेन पानी के अंदर दौड़ेगी. इस मेट्रो टनल को हुगली नदी के तल से 32 मीटर नीचे बनाया गया है. ये अंडर वॉटर मेट्रो टनल हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड सेक्शन के बीच में दौड़ेगी.

वहीं ये अंडरग्राउंड मेट्रो 45 सेकेंड में हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करेगी. इसके अलावा पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड मेट्रो सेक्शन, कवि सुभाष स्टेशन-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेक्शन और तारातला-माझेरहाट मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन भी किया.

रेल मंत्री ने दी जानकारी

इस अंडरवाटर मेट्रो सेवा को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि कोलकाता मेट्रो पर काम 1970 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति उससे पहले के 40 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान बुनियादी ढांचा तैयार करने और देश के लिए नींव तैयार करने पर है, जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होगा. कोलकाता मेट्रोका काम कई चरणों में आगे बढ़ा. मौजूदा चरण में शहर के ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए नदी के नीचे सुरंग बनाई गई है.

मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सैन्य अभ्यास

सैन्य अभ्यास 'टाइगर ट्राइंफ़ –24'

भारत और अमरीका के बीच स्थापित भागीदारी के अनुरूप, दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सैन्य अभ्यास, 'टाइगर ट्राइंफ़–24', 18 से 31 मार्च 24 तक पूर्वी समुद्र तट पर निर्धारित है। भारतीय नौसेना अभिन्न हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ जहाज, भारतीय नौसेना के विमान, भारतीय थलसेना के जवान और वाहन तथा भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर के साथ-साथ रैपिड एक्शन मेडिकल टीम (आरएएमटी) इस सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। अमरीका का प्रतिनिधित्व अमरिकी नौसेना के जहाजों द्वारा किया जाएगा, जिसमें अमरीकी मरीन कोर और अमरीकी थल सेना के सैनिक शामिल होंगे। सैन्य अभ्यास 'टाइगर ट्राइंफ – 24' का उद्देश्य एचएडीआर अभियानों के संचालन के लिए अंत:पारस्परिकता विकसित करना और दोनों देशों की सेनाओं के बीच तेजी से और सुचारू समन्वय को सक्षम करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में सुधार लाना है।

इस सैन्य अभ्यास का 'हार्बर चरण' 18 से 25 मार्च 24 तक निर्धारित है। दोनों देशों की नौसेनाओं के कर्मी प्रशिक्षण दौरों, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान, खेल आयोजनों और समाज के आम लोगों से बातचीत में भाग लेंगे। हार्बर चरण के पूरा होने पर भाग लेने वाले सैन्यकर्मी जहाजों के साथ 'टाइगर ट्राइंफ – 24' सैन्य अभ्यास के समुद्री चरण के लिए रवाना होंगे और बनाई गई स्थितियों के अनुसार समुद्री, उभयचर तथा एचएडीआर अभियानों के कामों को करेंगे।

LOK SHAKTI 25

वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य

"भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज मात्र 8 अरब (बिलियन) अमेरिकी डॉलर की है, लेकिन हमारा अपना अनुमान है कि 2040 तक यह कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उदाहरण के लिए अधिक रोचक बात यह है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के अनुसार हाल में ही जारी एडीएल (आर्थर डी लिटिल) रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हमारे पास 2040 तक 100 अरब (बिलियन) अमेरिकी डॉलर डॉलर की क्षमता हो सकती है"।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री अहमदाबाद में इन-स्पेस (आईएन-एसपीएसीई) के तकनीकी केंद्र का शुभारंभ करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस क्षेत्र को "गोपनीयता के पर्दे" से "बाहर निकालने (अनलॉक करने)" के साहसी निर्णय के बाद ही संभव हो पाई है।

उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए खोलकर अतीत की वर्जनाओं को तोड़ दिया है।"

केंद्रीय मंत्री ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को "अनलॉक" करके और एक सक्षम वातावरण प्रदान करके भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को उनके संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई के सपने को साकार करने में सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा श्रेय दिया, जिसमें भारत की विशाल क्षमता और प्रतिभा को एक अवसर (आउटलेट) मिल सकने के साथ ही शेष विश्व के आगे स्वयं को सक्षम सिद्ध किया जा सके।

उन्होंने कहा कि "भले ही देश में प्रतिभा की कभी कमी नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सक्षम वातावरण की लापता कड़ी को फिर से जोड़ा गया और अब अंतरिक्ष क्षेत्र के खुलने के साथ ही, आम जनता चंद्रयान-3 या आदित्य जैसे मेगा अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रक्षेपण को देखने में सक्षम हुई है"।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार-पांच साल पहले, हमारे पास अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ एक अंक के स्टार्टअप थे, आज इस क्षेत्र के खुलने के बाद हमारे पास लगभग 200 निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स हैं, जबकि उनमें से पहले वाले उद्यमी भी बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जारी वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर 2023 तक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स द्वारा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भले ही हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम वर्ष 1969 में उस समय शुरू हुआ था, जिस वर्ष अमेरिका ने चंद्रमा पर पहले मानव को उतारा था, फिर भी हम तेजी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले देशों के बराबर पहुंच गए और पिछले साल चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के अछूते दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर ऐतिहासिक लैंडिंग की जहां पहले कोई नहीं उतरा था।

मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंतरिक्ष बजट कई गुना बढ़ा दिया और अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया है।

"यदि आप अकेले अंतरिक्ष बजट को देखें, तो पिछले नौ वर्षों में 142 प्रतिशत की वृद्धि हुई है," उन्होंने कहा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे संबंधित बजटों में तीन गुना या अधिक बढ़ोतरी हुई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नवप्रवर्तकों (इनोवेटर्स), अनुसन्धान एवं विकास (आरएंडडी) और स्टार्टअप्स के लिए यह संभवतः सबसे अच्छा समय है। पीएम मोदी ने सही पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया है जो नवाचार का समर्थन करने के साथ ही उसे आगे बढ़ाता है तथा उद्यमशीलता का समर्थन करते हुए एक संपन्न उद्योग को भी बढ़ावा देता है।

"…और इसी ने बहुपक्षीय कई गुना निवेश जैसे परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए अब अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप्स - और उद्योग के बीच एक बड़ा समन्वयन हो गया है"।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1990 के दशक से इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 90 प्रतिशत से अधिक - 389 पिछले नौ वर्षों में प्रक्षेपित (लॉन्च) किए गए हैं। उन्होंने कहा कि "हमने अब तक विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से 17 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर कमाए हैं, इन 17 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर में से 15 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर पिछले नौ वर्षों में ही कमाए गए हैं... पिछले 30 वर्षों या उससे भी अधिक वर्षों में अब तक प्रक्षेपित (लॉन्च) किए गए यूरोपीय उपग्रहों में से, उत्पन्न कुल राजस्व 25 करोड़ 60 लाख यूरो है। पिछले नौ वर्षों में ही 22 करोड़ 30 लाख यूरो, लगभग 90 प्रतिशत, कमाया गया है, जिसका अर्थ है कि पैमाना बढ़ बढ़ने के साथ ही गति भी बढ़ गई है और इसलिए एक बड़ा उछाल आया है"।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की घोषणा की है, जो अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) की शुरू से अंत तक भागीदारी को सक्षम बनाती है।

"भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण प्रयासों को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भूमिका निर्विवाद है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र या इन -स्पेस (आईएन- एसपीएसीई) को अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का समर्थन करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और उसका समर्थन करने के लिए इन -स्पेस द्वारा अर्थात प्रारम्भिक निवेश निधि (सीड फंडिंग) योजना, मूल्य निर्धारण समर्थन नीति, मार्गदर्शन (मेंटरशिप) समर्थन, एनजीई के लिए डिजाइन प्रयोगशाला (लेबोरेटरी), अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास, भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो- आईएसआरओ) सुविधा उपयोग समर्थन एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एनजीई जैसी विभिन्न योजनाएं भी घोषित और कार्यान्वित की गई हैं"।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इन-स्पेस (आईएन-एसपीएसीई) ने ऐसे गैर-सरकारी संस्थाओं (नॉन-गवर्नमेंट एंटिटीज- एनजीईएस) द्वारा परिकल्पित अंतरिक्ष प्रणालियों और अनुप्रयोगों को साकार करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे एनजीईएस के साथ लगभग 45 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे प्रक्षेपण वाहनों (लॉन्च वेहिकल्स) और उपग्रहों के निर्माण में उद्योग की भागीदारी बढ़ने की बड़ी सम्भावना है।

"देश में अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित कई उद्योग संघ हैं, भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योग संघों द्वारा की जा रही गतिविधियाँ सरकार के दायरे में नहीं आती हैं"।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष मिशन मानव संसाधनों और कौशल पर आधारित लागत प्रभावी होने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वस्तुतः हर व्यक्ति के जीवन को छू रही है, जिसमें आपदा प्रबंधन, स्वामित्व, पीएम गति शक्ति, रेलवे, राजमार्ग और स्मार्ट शहर, कृषि, जल मानचित्रण, टेलीमेडिसिन और रोबोट द्वारा शल्य चिकित्सा जैसे बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

यह कहते हुए कि "अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ)" वैज्ञानिक अनुसंधान में एक बड़े सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का मार्ग प्रशस्त करेगा, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनआरएफ संयुक्त राज्य अमेरिका के एनआरएफ से बेहतर मॉडल होगा।

उन्होंने कहा कि "एनआरएफ बजट में पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण (फंडिंग) की परिकल्पना की गई है। जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत -70 प्रतिशत, गैर-सरकारी स्रोतों से आने का अनुमान है"।

यह दोहराते हुए कि ठहराव (साइलो) का युग समाप्त हो गया है, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनआरएफ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच एकीकरण की कल्पना करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पालिसी-एनईपी) - 2020 की अनुशंसाओं (रिकमंडेशंस) के अनुसार यह देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।

यह कहते हुए कि विश्व आज भारत के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज के युवा प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत @2047 के वास्तुकार होंगे।

एसएंडपी ने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी साल 2031 तक बढ़कर डबल हो जाएगी। इसका आकार 3.4 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 6.7 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा। रेटिंग एजेंसी ने अगस्त वॉल्यूम रिपोर्ट 'लुक फॉरवर्ड इंडिया मोमेंट' में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर यह जानकारी साझा की है। एजेंसी ने कहा है कि विनिर्माण और सेवाओं के निर्यात और उपभोक्ता मांग के कारण यह तेजी बनी रहेगी। एसएंडपी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी होने से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी। 2031 तक भारत पर कैपिटा जीडीपी 2500 से बढ़कर 4500 डॉलर तक हो जाएगी।

UBS ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर किया 6.3 प्रतिशत

ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस (UBS) ने मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है।

दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर 'यशोभूमि'

नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर 'यशोभूमि' का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। यह दुनिया के सबसे बड़े कन्वेशन सेंटर में से एक है। इसकी लागत लगभग 5400 करोड़ रुपये है और यह 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक जमीन पर बना है। यशोभूमि में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं हैं जो विश्वस्तरीय हैं और दुनिया के किसी भी देश के कन्वेंशन सेंटर से टक्कर ले सकते हैं। इसमें 11000 प्रतिनिधियों से अधिक की बैठने की क्षमता है। कन्वेंशन सेंटर के साथ इसमें 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष भी शामिल हैं। यह सीधा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से भी जुड़ा हुआ है और पीएम ने यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन किया। यह दुनिया के सबसे बड़े MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन) सेंटर्स में से एक है और इसके बनने के साथ ही वैश्विक स्तर पर मीटिंग, प्रदर्शनी और कन्वेंशन में अब सहायता मिलेगी।

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर 'यशोभूमि' का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। यह दुनिया के सबसे बड़े कन्वेशन सेंटर में से एक है। इसकी लागत लगभग 5400 करोड़ रुपये है और यह 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक जमीन पर बना है। यशोभूमि में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं हैं जो विश्वस्तरीय हैं और दुनिया के किसी भी देश के कन्वेंशन सेंटर से टक्कर ले सकते हैं। इसमें 11000 प्रतिनिधियों से अधिक की बैठने की क्षमता है। कन्वेंशन सेंटर के साथ इसमें 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष भी शामिल हैं। यह सीधा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से भी जुड़ा हुआ है और पीएम ने यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन किया। यह दुनिया के सबसे बड़े MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन) सेंटर्स में से एक है और इसके बनने के साथ ही वैश्विक स्तर पर मीटिंग, प्रदर्शनी और कन्वेंशन में अब सहायता मिलेगी। भारत मंडपम में लगाई गई नटराज की यह मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 27 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। वहीं इस मूर्ति का वजन लगभग 18 टन है। इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स तकनीक के माध्यम से अष्टधातु से बनाया गया है। इस मूर्ति का निर्माण श्री राधाकृष्णण की अगुआई में शिल्प शास्त्र में लिखे गए सभी नियमों और सिद्धातों का पालन करते हुए किया गया है। इस प्रतिमा को जिस लॉस्ट वैक्स तकनीक के माध्यम से बनाया गया है, उसका पालन चोल काल से किया जा रहा है। शिव नटराज की यह मूर्ति अनंत शक्ति का प्रतीक है। ईश्वर का यह स्वरूप धर्म, दर्शन, कला, शिल्प और विज्ञान का समन्वय है। चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को 41 दिन की चंद्रमा की यात्रा पर रवाना हुआ था और 23 अगस्त 2023 को इसने सफल 'सॉफ्ट लैंडिंग' की। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह पर सफल 'सॉफ्ट लैंडिंग' करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।

भारत से पहले चांद पर पूर्ववर्ती सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ही सफल 'सॉफ्ट लैंडिंग' कर पाए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' नहीं कर पाया है, और अब भारत के नाम इस उपलब्धि को हासिल करने का रिकॉर्ड हो गया है। 4 साल में भारत के दूसरे प्रयास में चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के लैंडर 'विक्रम' ने 26 किलोग्राम के रोवर 'प्रज्ञान' के साथ योजना के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक 'सॉफ्ट लैंडिंग' की। इस तरह इस टेक्नोलॉजी में भारत ने महारत हासिल कर ली और इसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है।

Plant

सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन: देश को यूरिया के मामले में बनाएंगे आत्मनिर्भर

पबता दें कि इस संयंत्र से देश में प्रति वर्ष लगभग 12.7 एलएमटी (लाख मीट्रिक टन) स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा, जिससे देश के किसानों को लाभ होगा। गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक संयंत्रों के कायाकल्?प के बाद यह देश में दोबारा चालू होने वाला तीसरा उर्वरक संयंत्र है। गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक संयंत्रों को क्रमश: दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने झारखंड में 17,600 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें में सोन नगर-अंडाल को जोडऩे वाली तीसरी और चौथी लाइन, टोरी-शिवपुर पहली और दूसरी तथा बिराटोली-शिवपुर तीसरी रेलवे लाइन (टोरी-शिवपुर परियोजना का हिस्सा), मोहनपुर-हंसडीहा नयी रेल लाइन, धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन शामिल हैं। इन परियोजनाओं से राज्य में रेल सेवाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।

मोदी झारखंड पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने 35,700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि इन परियोजनाओं में 8900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) का सिंदरी उर्वरक संयंत्र भी शामिल है जो यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है।

क्या बोले पीएम मोदी

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के युवाओं के लिए ये रोजगार की शुरुआत है। इसके साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत की ओर उठाया गया एक कदम है। हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़ा है। गोरखपुर और रामागुंडम के साथ ही अब सिन्द्री का भी नाम जुड़ गया है। आज का दिन झारखंड में रेल क्रांति का एक नया अध्याय लिख रहा है। रेलवे के कई प्रोजेक्ट आज यहां पर शुरू हो रहे हैं। बीते 10 वर्षों में हमने जनजातिय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता में रखकर काम किया है। हमें 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है।

भारत ने UNSC में सुधार के लिए पेश किया G-4 देशों का विस्तृत मॉडल, इन देशों को सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनाने का प्रस्ताव

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जी4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल पेश किया, जिसमें महासभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से नए स्थायी सदस्यों को चुने जाने और वीटो के मामले पर लचीलेपन को अपनाए जाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) के दौरान कहा कि अगले साल होने वाली संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ काफी समय से लंबित विषय पर ठोस प्रगति करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है।

कंबोज ने ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की ओर से बहस, संवाद और अंतत: बातचीत के लिए 'जी4 मॉडल' पेश किया। इन प्रस्तावों को बड़े पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र सदस्यों से मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ। कंबोज ने महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ विस्तृत जी4 मॉडल साझा करते हुए कहा, ''जब 1945 में परिषद की स्थापना की गई थी, तब की वास्तविकताएं, आधुनिक युग और नई सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से काफी समय पहले बदल गई हैं और इसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है।'' उन्होंने कहा कि इन नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए जी4 मॉडल का प्रस्ताव है कि छह स्थायी और चार या पांच गैर-स्थायी सदस्यों को जोड़कर सुरक्षा परिषद की सदस्यता मौजूदा 15 से बढ़कर 25-26 की जाए।

सुरक्षा परिषद में दो अफ्रीकी देशों और दो एशिया प्रशांत देशों, एक लातिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई देश तथा पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य क्षेत्रों से एक देश को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। जी4 मॉडल के अनुसार, सदस्यता की दोनों श्रेणियों में प्रमुख क्षेत्रों के ''स्पष्ट रूप से कम प्रतिनिधित्व और गैर-प्रतिनिधित्व'' के कारण सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना इसकी वैधता और प्रभावशीलता के लिए ''हानिकारक'' है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि संघर्षों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में परिषद की असमर्थता सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। कंबोज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जी4 मॉडल यह ''नहीं बताता'' कि कौन से देश नए स्थायी सदस्य होंगे और ''यह निर्णय लोकतांत्रिक और समावेशी तरीके से चुनाव के जरिये महासभा करेगी।'' जी4 मॉडल के तहत वीटो को लेकर लचीलेपन की पेशकश की गई।

वीटो पर कही गई ये बात - वीटो का मामला सदस्य देशों के बीच विवाद का विषय रहा है। कंबोज ने कहा, ''हालांकि नए स्थायी सदस्यों की जिम्मेदारियां एवं दायित्व सैद्धांतिक रूप से वर्तमान स्थायी सदस्यों के समान ही होंगे, लेकिन वे तब तक वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि समीक्षा के दौरान मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।'' उन्होंने कहा, ''बहरहाल, हमें वीटो मुद्दे को परिषद सुधार की प्रक्रिया पर ''वीटो'' की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमारा प्रस्ताव रचनात्मक बातचीत के लिए इस मुद्दे पर लचीलापन प्रदर्शित करने का एक संकेत भी है।' वर्तमान में, केवल पांच स्थायी सदस्यों- चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका- के पास वीटो शक्ति है। उन्होंने इसका इस्तेमाल कर यूक्रेन और गाजा जैसी वैश्विक चुनौतियों और संघर्षों से निपटने संबंधी परिषद की कार्रवाई को बाधित किया है।

गैर स्थाई सदस्यों के पास नहीं होती वीटो शक्ति - परिषद में शेष 10 देशों को दो साल के कार्यकाल के लिए गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में चुना जाता है और उनके पास वीटो शक्ति नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि निकोलस दे रिविएर ने कहा कि उनका देश लंबे समय से स्थायी सदस्यता के लिए भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी की उम्मीदवारी का समर्थन करता रहा है।

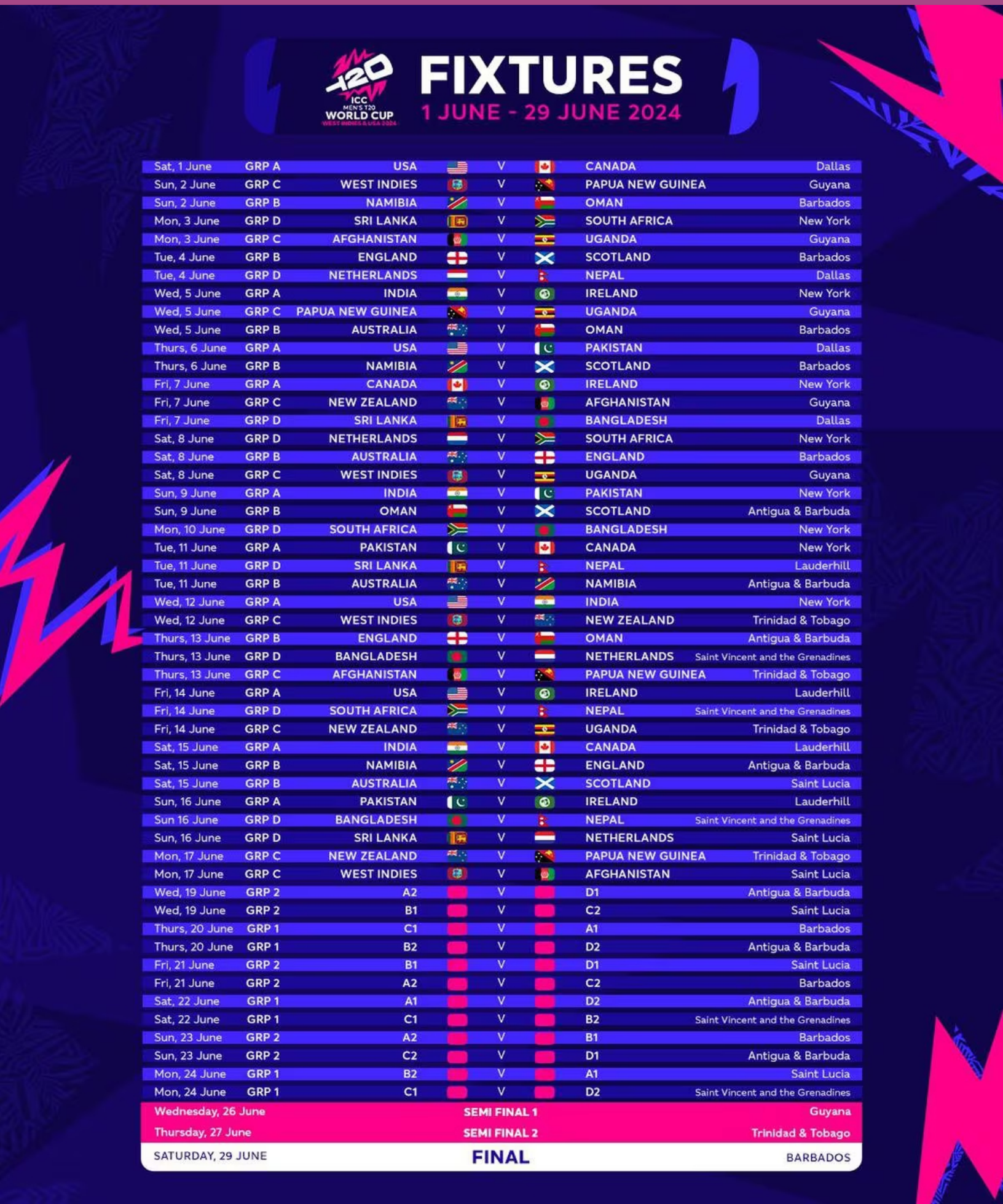
T20
ICC
MEN'S T20
WORLD CUP
WEST INDIES & USA 2024
FIXTURES
1 JUNE - 29 JUNE 2024
Sat, 1 June GRP A USA V CANADA Dallas
Sun, 2 June GRP C WEST INDIES V PAPUA NEW GUINEA Guyana
Sun, 2 June GRP B NAMIBIA V OMAN Barbados
Mon, 3 June GRP D SRI LANKA V SOUTH AFRICA New York
Mon, 3 June GRP C AFGHANISTAN V UGANDA Guyana
Tue, 4 June GRP B ENGLAND V SCOTLAND Barbados
Tue, 4 June GRP D NETHERLANDS V NEPAL Dallas
Wed, 5 June GRP A INDIA V IRELAND New York
Wed, 5 June GRP C PAPUA NEW GUINEA V UGANDA Guyana
Wed, 5 June GRP B AUSTRALIA V OMAN Barbados
Thurs, 6 June GRP A USA V PAKISTAN Dallas
Thurs, 6 June GRP B NAMIBIA V SCOTLAND Barbados
Fri, 7 June GRP A CANADA V IRELAND New York
Fri, 7 June GRP C NEW ZEALAND V AFGHANISTAN Guyana
Fri, 7 June GRP D SRI LANKA V BANGLADESH Dallas
Sat, 8 June GRP D NETHERLANDS V SOUTH AFRICA New York
Sat, 8 June GRP B AUSTRALIA V ENGLAND Barbados
Sat, 8 June GRP C WEST INDIES V UGANDA Guyana
Sun, 9 June GRP A INDIA V PAKISTAN New York
Sun, 9 June GRP B OMAN V SCOTLAND Antigua & Barbuda
Mon, 10 June GRP D SOUTH AFRICA V BANGLADESH New York
Tue, 11 June GRP A PAKISTAN V CANADA New York
Tue, 11 June GRP D SRI LANKA V NEPAL Lauderhill
Tue, 11 June GRP B AUSTRALIA V NAMIBIA Antigua & Barbuda
Wed, 12 June GRP A USA V INDIA New York
Wed, 12 June GRP C WEST INDIES V NEW ZEALAND Trinidad & Tobago
Thurs, 13 June GRP B ENGLAND V OMAN Antigua & Barbuda
Thurs, 13 June GRP D BANGLADESH V NETHERLANDS Saint Vincent and the Grenadines
Thurs, 13 June GRP C AFGHANISTAN V PAPUA NEW GUINEA Trinidad & Tobago
Fri, 14 June GRP A USA V IRELAND Lauderhill
Fri, 14 June GRP D SOUTH AFRICA V NEPAL Saint Vincent and the Grenadines
Fri, 14 June GRP C NEW ZEALAND V UGANDA Trinidad & Tobago
Sat, 15 June GRP A INDIA V CANADA Lauderhill
Sat, 15 June GRP B NAMIBIA V ENGLAND Antigua & Barbuda
Sat, 15 June GRP B AUSTRALIA V SCOTLAND Saint Lucia
Sun, 16 June GRP A PAKISTAN V IRELAND Lauderhill
Sun 16 June GRP D BANGLADESH V NEPAL Saint Vincent and the Grenadines
Sun, 16 June GRP D SRI LANKA V NETHERLANDS Saint Lucia
Mon, 17 June GRP C NEW ZEALAND V PAPUA NEW GUINEA Trinidad & Tobago
Mon, 17 June GRP C WEST INDIES V AFGHANISTAN Saint Lucia
Wed, 19 June GRP 2 A2 V D1 Antigua & Barbuda
Wed, 19 June GRP 2 B1 V C2 Saint Lucia
Thurs, 20 June GRP 1 C1 V A1 Barbados
Thurs, 20 June GRP 1 B2 V D2 Antigua & Barbuda
Fri, 21 June GRP 2 B1 V D1 Saint Lucia
Fri, 21 June GRP 2 A2 V C2 Barbados
Sat, 22 June GRP 1 A1 V D2 Antigua & Barbuda
Sat, 22 June GRP 1 C1 V B2 Saint Vincent and the Grenadines
Sun, 23 June GRP 2 A2 V B1 Barbados
Sun, 23 June GRP 2 C2 V D1 Antigua & Barbuda
Mon, 24 June GRP 1 B2 V A1 Saint Lucia
Mon, 24 June GRP 1 C1 V D2 Saint Vincent and the Grenadines
Wednesday, 26 June SEMI FINAL 1 Guyana
Thursday, 27 June SEMI FINAL 2 Trinidad & Tobago
SATURDAY, 29 JUNE FINAL BARBADOS

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हमने बनाया है
हम ही संवारेंगे

मोदी की गारंटी
विष्णु का सुशासन

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

त्वरित निर्णय के 2 माह

अन्नदाताओं के लिए

- 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने का निर्णय
- किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय
- 'कृषक उन्नति योजना' के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

ग्रामीणों के लिए

- 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान

गरीबों के लिए

- 69.92 लाख गरीब परिवारों को पांच वर्षों तक निःशुल्क राशन प्रदाय का निर्णय
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 'दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना' में खेतिहर मजदूरों को 10,000 रुपये वार्षिक सहायता का निर्णय

महिलाओं के लिए

- 'महतारी वंदन योजना' के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की दर से वार्षिक 12,000 रुपए आर्थिक सहायता का निर्णय

युवाओं के लिए

- पीएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच का निर्णय
- युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना लागू करने का निर्णय
- पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट का निर्णय

सभी छत्तीसगढ़वासियों के लिए

- अयोध्या यात्रा के लिए 'रामलला दर्शन योजना' लागू करने का निर्णय

आदिवासियों के लिए

- तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा भुगतान का निर्णय

छत्तीसगढ़ के त्वरित विकास के लिए

- कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान

सामान्य परिवारों के लिए

- प्रति माह 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदाय का निर्णय

भ्रष्टाचार निवारण के लिए

- शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 'अटल मॉनिटरिंग पोर्टल' की स्थापना का निर्णय
- कोल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट व्यवस्था लागू करने का निर्णय

छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए

- छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थल राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) के आयोजन का निर्णय

NAMO app
डाउनलोड करने के लिए
यह क्यूआर कोड स्कैन करें

मुख्यमंत्री कार्यालय का
व्हाट्सएप चैनल
सब्सक्राइब करने के लिए
यह क्यूआर कोड स्कैन करें

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

R.O. No.- 12756/ 208

Owner, Printer, Publisher & Editor- Premendra Agrawal, Published from 5/756, Desh Bandhu Press Road, Behind Sindhi School, Raipur (C.G.) - 492001
& Printed at Commercial Services, Ramsagarpara, Raipur (C.G.)